हुए कपड़े, जूते, लौंग, घड़ियां व सूखे मेवा आदि की तस्करी होती है।

विशेष डाकू के मारे जाने के कारण ग्रामवासियों को भय है कि बदला लेने के लिए पाकिस्तानी दस्युओं द्वारा उन पर दुबारा कातिला हमला होगा। अतः इस गम्भीर समस्या पर गृह-मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि ये वक्तव्य द्वारा स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

(viii) DEMAND FOR RELIEF MEASURES INCLUDING REBATE IN EXCISE DUTY TO TEA GROWERS IN KERALA

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): The tea industry is an agriculture based industry, which is highly labour intensive. The workers are mainly Scheduled Castes Scheduled Tribes and other weaker sections. Over 50 per cent of the workers are women, besides a large number of children. This is situated in the remote areas. This industry should have been declared as priority sector.

In Kerala, tea is produced in an area of 36,150 hectares i.e. 48 per cent of the total area in South India and 9.8 per cent of the total area in India. It provides direct employment to one lakh people, besides a much larger number is engaged in allied and auxiliary activities. The Kerala Government has granted certain tax reliefs by reducing sales tax by 50 per cent, suspending sales tax on fertilisers and exempting tea from 20 per cent increase in plantation tax. Considering the cost of production, these reliefs have to be continued with more and effective concessions, exemptions and assistance from the Centre. While the cost of production is going up, the prices and production are gowing down. It is said that producers incur a loss of Rs. 2/- per kg. The relief announced by the Centre are (a) full rebate of excise duty on tea exported directly from the gardens; (b) rebate of excise duty of 44 paise per kg. on export of tea by merchant-exporters; and (c) drawback of customs/excise duty on packing materials like aluminium foils, plywood etc., etc. used in export of tea. These benefits are only for the exporters and not for the producers or workers. There is very very little export by the producers. 73 per cent of Kerala tea is sold in auction. These producers have no infrastructure or ability to export directly. This is the situation in all the States in the South.

I submit that among all the States, Kerala is the worst hit by this crisis. The State of Kerala alone is not able to give all the help. A straight reduction of excise duty (which forms an essential part of the recommendations of the National Tea Meet) will benefit the crisis-ridden industry to a certain degree. 63 per cent of tea area of Kerala comes under Zone 1 with an excise duty of 44 paise per kg.

Therefore, I appeal to the Government to give straight reduction of excise duty of at least 44 paise per kg., see that the announced relief of rebates on export goes to the producers and declare the tea industry as a priority sector and also to save the tea industry of India efficient and calculated measures are required to be resorted to immediately. Especially a machinery for coordination of tea policy, administration and organisation of the Centre/State efforts must be constituted and all efforts should be made forthwith to help the sick tea industry of India.

(ix) CONSTRUCTION OF MEMORIALS IN THE MEMORY OF FREEDOM FIGHTERS

श्री रामलाल राही (मिसरिख): उपाध्यक्ष महोदय, आज ऐसे वक्त से

स्वतन्त्रता सेनानी हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। वे आजीविकाअर्जन के लिए शारीरिक रूप से अस्यन्त दुर्बल हो गए हैं। सैनिक-सम्मान-पेंशन योजना के अधीन सरकार से मिल सकने वाली अत्यल्प राशि के लिए भी उन्हें दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में जांच करनी चाहिए, ताकि उपर्युक्त पेंशन की राशि और सहायता इन व्यक्तियों को निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त कराई जा सके। ऐसा न करके सरकार ने इन स्वतन्त्रता-सेनानियों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित नहीं की है। इस समस्या को उपर्युक्त पेंशन की वितरण प्रक्रिया में सुधार ला कर हल किया जा सकता है।

उन असख्य स्वतन्त्रता-सेनानियों में से, जिन्होंने स्वतन्त्रता-संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा अमूल्य रोगदान दिया, केवल कुछ ही के नाम इतिहास में स्थान पा सके हैं और केवल कुछ ही सेनानियों के स्मारक बन सके हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए हैं, जिनका जीवन राष्ट्रीयता से परिपूर्ण था और वे न केवल वर्तमान बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। मेरे विचार से यदि सरकार ने स्वतन्त्रता-सेनानियों की स्मृति में स्थानित रूप से स्मारकों का निर्माण किया होता, तो वर्तमान और भावी पीढ़ियां उनके नि:स्वार्थ जीवन से प्रेरणा प्राप्त करतीं और जनसाधारण में एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा होती तथा उन लोगों को राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपने कर्त्तव्यों तथा दायित्वों का बोध होता हैं।

हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र के सुदूरवर्ती स्थानों में बड़े और छोटे पुलों, सड़कों, नहरो तथा बांधों के निर्माण जैसे बहुत से महत्व-पूर्ण निर्माण कार्य किए गए हैं और शिक्षा संस्थाओं तथा अनुसंधान संस्थानों की स्थापना हुई है। यहीं नहीं, "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम तथा अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत अनेक मांघों को जोड़ने वाली बहुत सी महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन सार्वजनिक सड़कों, पुलों; संस्थाओं आदि के नाम दिवंगत स्वतन्त्रता-सेनानियों के नामों पर रखे जाएं। इस काम का शुभारम्भ 15 अगस्त, 1982 से होना चाहिए।

मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूँ कि वह इन स्वतन्त्रता-सेनानियों का एक इतिहास भी तैयार करे, जो ग्राम सभाओं अथवा स्थानीय सार्वजनिक संस्थाओं अथवा प्राथमिक विद्यालयों में रखा जाए। इन स्वतन्त्रता-सेनानियों के जीवन-चरित्र को स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक का पाठ्क्रयम अंग बनाया जाए। वस्तुत: इसी प्रकार हमारे देश की जनता अपने प्रतिष्ठित स्वतन्त्रता-सेनानियों के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगी।

अत : सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे इन सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु युद्ध-स्तर पर कार्य करे और इस सम्बन्ध में कार्यारम्भ के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को निर्देश दे।